

district/block with due regard to the felt needs of the rural community. To ensure durability of assets and to avoid taking up of katcha works, the ratio of non-wage expenditure under the programme has been raised to 50 per cent from 40 per cent. The ceiling of 50 per cent has also been made applicable to district as a whole instead of individual works as done earlier.

#### **Sugarcane Development Schemes**

\*955. SHRI K.A. SWAMI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have initiated any sugarcane development schemes; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI RAO BIRENDRA SINGH) : (a) A Centrally Sponsored Scheme on the development of sugarcane during the Sixth Five Year Plan period, is in operation only in the Union Territories of Goa and Pondicherry with total Central assistance. In addition, in the first year of the Sixth Five Year Plan (1980-81), Central assistance was provided to sugarcane producing States for plant protection chemicals to boost the sugarcane production which had slumped to 1288.33 lakh tonnes in 1979-80.

(b) The Centrally Sponsored Scheme on sugarcane development in the Union Territories of Goa and Pondicherry provides assistance for demonstrations and training of cane development workers. For 1984-85, an amount of Rs. 2.40 lakh has been provided under this scheme.

#### **Financial Assistance to Agricultural Universities in Madhya Pradesh by I.C.A.R.**

\*956. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether ICAR has given financial assistance to Agricultural Universities in Madhya Pradesh for establishment and construction work during the last three years;

(b) whether any new Agricultural University/Veterinary Institute or new Regional Stations and Centres are planned by ICAR in Madhya Pradesh; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Yes, Sir. The Indian Council of Agricultural Research has been giving financial assistance to Jawaharlal Nehru Krishi Vishva Vidyalaya, Jabalpur (Madhya Pradesh) during the last three years for development, including construction work, under the scheme "Establishment and Development of Agricultural Universities". Financial assistance is also being given to the university under the 'National Agricultural Research Project' to strengthen its regional research capabilities covering construction work also.

(b) No new Agricultural University is proposed to be established in the State during the VI Plan. It is, however, proposed to establish a High Security Animal Disease Laboratory at Bhopal with United Nations Development Programme, assistance. It is also proposed to establish/strengthen four Regional Research Stations at Jabalpur, Jabalpur, Rewa and Indore under the National Agricultural Research Project.

(c) The High Security Animal Disease Laboratory is meant for conducting research work on such animal and poultry diseases which are exotic in nature. An officer of Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar has already been appointed as officer-on-Special Duty to establish this laboratory.

The Jawaharlal Nehru Krishi Vishva Vidyalaya, Jabalpur has been requested to submit suitable proposals for strengthening/establishing the regional

research stations at the 4 locations mentioned.

सहकारी क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए विश्व बैंक की वित्तीय सहायता

957. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए विश्व बैंक द्वारा राज्यवार, कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा उन गोदामों की संख्या क्या है जिनके लिए यह सहायता दी गई;

(ख) इसमें से राज्य-वार कितनी सहायता राशि का उपयोग किया गया तथा कितने गोदामों का निर्माण किया गया; और

(ग) लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल न करने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) विश्व बैंक के साथ किये गये करार में, जिसने सहकारी समितियों द्वारा गोदाम के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है, कवर किये गये राज्यों में बनाए जाने वाले गोदामों की कुल संख्या का हवाला दिया गया है और विश्व बैंक निधि का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता। विश्व बैंक की सहायता की मात्रा गोदामों की कुल लागत के 47 प्रतिशत तक सीमित है और शेष धनराशि राष्ट्रीय सहकारी प्राप्त विकास निगम, राज्य सरकारों और लाभ करने वाली सहकारी समितियों द्वारा पूरी की जाती है। गोदामों के निर्माण में वास्तविक प्रगति, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि और वह धनराशि, जिसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास

निगम ने विश्व बैंक से अदायगी के लिए दावा किया है, को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) गोदामों की लागत में वृद्धि होने के कारण विश्व बैंक के परामर्श से समय-समय पर वास्तविक लक्ष्यों में संशोधन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-1 परियोजना, जिसमें 1979-84 तक की अवधि शामिल है, के अंतर्गत गोदामों के निर्माण संबंधी संशोधित लक्ष्य बहुत संतोषजनक हैं। तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-2 परियोजना, जिसमें 1981-87 तक की अवधि शामिल है, के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब होने, पर्याप्त मात्रा में लेवी सीमेंट उपलब्ध न होने, दूरदराज के गांवों में लघु कार्य करने में ठेकेदारों की रुचि न होने और निरीक्षण कर्मचारी पर्याप्त न होने की वजह से गोदामों के निर्माण की गति में पूरी तरह से तेजी नहीं आयी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम परियोजना के क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए कार्यवाही कर रहा है।

### विवरण

विश्व बैंक ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-1 सहकारी भण्डारण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 300 लाख अमरीकी डालर (जो कि 26.65 करोड़ रुपए के बराबर है) के अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण की मंजूरी दी है। इसमें से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 31 मार्च, 1984 तक परियोजना के क्रियान्वयन पर वहन किये गये व्यय के आधार पर 25.57 करोड़ रुपए की धनराशि का दावा कर चुकी है। परियोजना की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 1984 है, जिस समय तक कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के समूचे ऋण को निकाला जाना और वितरित किया जाना है।